नक्सल-मुक्त भारत : एक निर्णायक रणनीतिक बदलाव

कुलदीप सिंह

'नक्सल-मुक्त भारत' की कहानी केवल सैन्य या पुलिस की कामयाबी तक सीमित नहीं है। यह समन्वित शासन प्रबंधन की एक मिसाल है। यह दर्शाती है कि किस प्रकार राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, पेशेवर सुरक्षा अभियान और विकास के प्रति प्रतिबद्धता मिलकर लंबे समय से चली आ रही उग्रवादी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे समाप्त कर सकते हैं।

नक्सल-मुक्त भारत का दृष्टिकोण सुरक्षा लक्ष्य के उद्देश्य से कहीं ज़्यादा है। यह नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में सुशासन बहाल करने, विकास को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नक्सलवाद दशकों तक भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक बना रहा जिसने (नक्सल) विकास कार्यों को बाधित कर, सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाकर और सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों का फायदा उठाकर मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को प्रभावित किया। हालांकि, हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। गृह मंत्रालय ने निरंतर सुरक्षा अभियानों, केंद्र-राज्यों के बीच मज़बूत समन्वय, विकास आधारित योजनाओं और रणनीतिक नेतृत्व के माध्यम से नक्सल खतरे को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

इस बदलाव के केंद्र में यह समझ थी कि नक्सल चुनौती से केवल बल प्रयोग के ज़रिए नहीं निपटा जा सकता। इसके

लेखक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। सीआरपीएफ में एडीजी और एसडीजी-सेंट्रल ज़ोन के पद पर रहते हुए वर्ष 2017 से 2021 के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कई बड़े नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया। वर्तमान में वे मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। ईमेलः advisorsec.manipur@gmail.com

लिए सुरक्षा अभियानों के साथ सुशासन, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ते हुए 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' यानी समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाया गया। यद्यपि क़ानून-व्यवस्था संवैधानिक रूप से 'राज्य' का विषय है और नक्सल विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस अग्रिम मोर्चे पर रही, लेकिन गृह मंत्रालय ने रणनीतिकार, समन्वयक और बल गुणक (फोर्स मल्टीप्लायर) की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अंतर महत्वपूर्ण है कि अभियान का संचालन राज्यों ने किया, लेकिन इसकी संरचनात्मक और रणनीतिक दिशा भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने तय की।

गृह मंत्रालय ने मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को खत्म करने के उद्देश्य से 'समाधान' SAMADHAN-सिद्धांत (S-स्मार्ट लीडरशिप, A-एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, M-मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A-एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D-डैशबोर्ड बेस्ड केआरए एंड केपीआई, H-हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A-एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर, N-नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग) के माध्यम से एक बहुआयामी, ज़ीरो टॉलरेंस नीति तैयार की। मार्च 2026 तक, सुरक्षा बलों ने उन्नत ख़ुफ़िया जानकारी, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और 'रेड कॉरिडोर' में विकास के माध्यम से लगभग सभी सीपीआई (माओवादी) नेतृत्व को निष्क्रिय कर दिया और अब 'ग्रोथ कॉरिडोर' पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

मुख्य परिवर्तनकारी रणनीतियां और कार्यनीति (2014-2026)

नेतृत्व और नीति परिवर्तन

गृह मंत्रालय के तहत अपनाई गई ज़ीरो-टॉलरेंस नीति में प्रतिक्रियात्मक कदमों के बजाय सक्रिय अभियानों पर ज़ोर दिया गया, जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को मिलने वाले वैचारिक, वित्तीय और रसद संबंधी समर्थन को समाप्त करना था। वहीं गृह मंत्रालय के एलडब्ल्यूई विभाग ने एक 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015)' लागू की, जिसमें "ट्रेस, टारगेट, न्यूट्रलाइज" रणनीति को प्राथमिकता दी गई। साथ ही विकास और सुरक्षा के समन्वय को इसके प्रमुख परिणाम के रूप में निर्धारित किया गया।

फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसः सुरक्षा नियंत्रण का विस्तार

नक्सलवाद के खिलाफ हालिया सफलता की एक प्रमुख विशेषता केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) - मुख्य रूप से सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) (जिसमें कोबरा - कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन यूनिट्स शामिल हैं), बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल), आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) और एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) की बढ़ी हुई भूमिका रही है। इन सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियानों की रीढ़ के रूप में कार्य करते हुए राज्य पुलिस को मारक क्षमता, ख़ुफ़िया जानकारी और रणनीतिक सहयोग प्रदान किया।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) विरोधी अभियानों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के रूप में सीआरपीएफ (विशेष रूप से कोबरा बटालियन) ने नक्सल प्रभावित इलाकों में फिर से नियंत्रण स्थापित करने, उग्रवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने और घने जंगलों में टारगेटेड अभियान चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन इलाकों में माओवादी समूहों को पारंपरिक रूप से सामरिक लाभ प्राप्त होता था।

नक्सल प्रभावित इलाकों में उग्रवादियों की पकड़ कमज़ोर करने और उनके लिए सुरक्षा शून्य पैदा करने के उद्देश्य से 350 से अधिक सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। इन कैंपों में

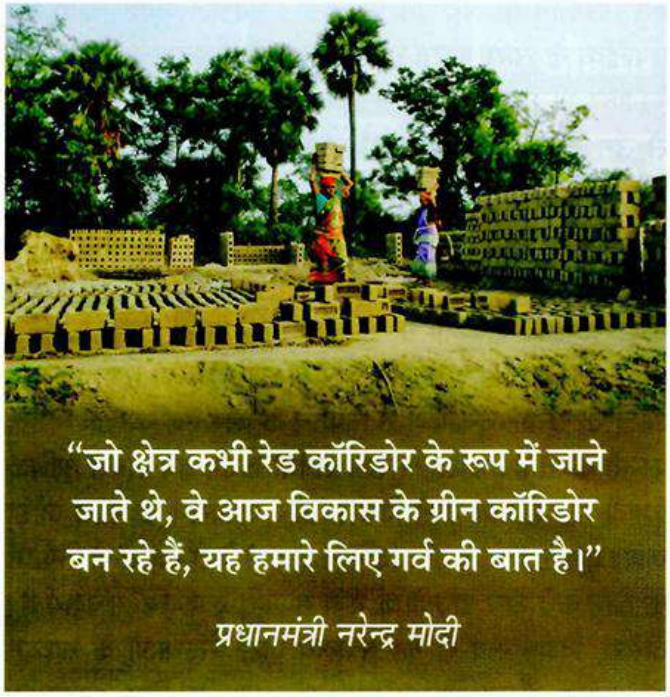

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ-साथ राज्य पुलिस की विशेष इकाइयां भी शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड, महाराष्ट्र के सी-60 कमांडो, ओडिशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और झारखंड के जैगुआर बल प्रमुख हैं। इन संयुक्त सुरक्षा कैंपों की भूमिका सिर्फ अभियानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा नियंत्रण मज़बूत करने, सड़कों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों की रक्षा करने और दुर्गम इलाकों में प्रशासन की वापसी में अहम योगदान दिया। सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत होने के बाद इन इलाकों में फिर से स्कूल खुलने लगे, सड़कें बनने लगी, और दूरदराज़ के गाँवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँची और सरकारी योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचना संभव हो सका।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) का भौगोलिक प्रसार 2014 में प्रभावित 126 ज़िलों से घटकर 2025 में केवल 11 रह गया है, और इसी अवधि में सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों की संख्या 36 से घटकर छह हो गई है।

आक्रामक अभियानों से नक्सली नेतृत्व पर निर्णायक प्रहार

अब रणनीति निष्क्रिय रोकथाम से आगे बढ़कर आक्रामक और सक्रिय अभियानों पर केंद्रित हो गई है। संयुक्त ऑपरेशन बेस (350 से अधिक) की स्थापना के साथ, 'ऑपरेशन ऑक्टोपस', 'ऑपरेशन डबल-बुल' और 'ऑपरेशन बूढ़ा पहाड़' चलाया गया। इन ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सली नेतृत्व और उनकी कमांड संरचना को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, परिणामस्वरूप 2025 में 300 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया और 200 से अधिक को गिरफ्तार किया गया। सीपीआई (माओवादी) के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें 21 टॉप लीडर्स में से 12 को मार गिराया गया, सात ने आत्मसमर्पण किया और एक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक नेता अभी भी फरार है।

राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर नज़र बनाए रखने में गृह मंत्रालय की नेतृत्वकारी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उग्रवाद-विरोधी अभियान अक्सर तब विफल हो जाते हैं जब ध्यान अस्थायी या बिखरा हुआ होता है। इसके विपरीत, नक्सल-विरोधी रणनीति को निरंतरता, नियमित निगरानी और स्पष्ट रूप से तय लक्ष्यों का लाभ मिला है। इस निरंतर संस्थागत प्रयास ने यह सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा अभियानों के माध्यम से प्राप्त लाभों को शासन और विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए।

"समग्र सरकारी दृष्टिकोण" के माध्यम से प्रभावी ऑपरेशनल समन्वय हासिल किया गया है, जिससे दूरदराज़ के इलाकों में सुरक्षा की कमी दूर हुई है। मल्टी-एजेंसी सेंटर को सभी सुरक्षा बलों को रियल टाइम ख़ुफ़िया जानकारी प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। सीएपीएफ और राज्य पुलिस बलों के बीच अभियानों में बेहतर तालमेल बैठाने के उद्देश्य से 15 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स गठित किए गए हैं। माओवादियों के वित्तीय संसाधनों को सीमित करने के लिए गृह मंत्रालय में (वर्ष 2016) दो मल्टी डिसिप्लिनरी समूह भी स्थापित किए गए हैं, परिणामस्वरूप करीब 40 करोड़ रुपये ज़ब्त किए जा चुके हैं।

'नक्सल-मुक्त भारत' की दिशा में एक और महत्वपूर्ण रणनीति केवल हथियारबंद नक्सलियों को निशाना बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उग्रवाद के पूरे समर्थन तंत्र और ढांचों को खत्म करने की भी रही। भर्ती, रसद, ज़बरन वसूली नेटवर्क और प्रचार मशीनरी को बाधित करने के प्रयासों ने माओवादी समूहों की संगठनात्मक क्षमता को कमज़ोर कर दिया। साथ ही, आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों ने नक्सली कैडरों को मुख्यधारा में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे उग्रवाद की ताकत और भी कम हो गई है।

सुरक्षा के साथ विकास और अधिकारों का समावेश

गृह मंत्रालय की रणनीतिक दिशा एक बहु-आयामी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दी है जिसमें सुरक्षा, विकास, अधिकार और सुविधाएं तथा जनसंपर्क को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई गई। इसके अंतर्गत राज्यों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, प्रभावित ज़िलों में बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, दूरसंचार, कौशल विकास, शिक्षा और बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं ने सीधे तौर पर उन परिस्थितियों को कमज़ोर किया, जिनका फायदा उग्रवादी संगठन उठाने की कोशिश करते थे।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) में 155 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और पिछले 11 वर्षों में परिचालन आवश्यकताओं, प्रशिक्षण और आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास के लिए 3,371 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी तरह, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) में विशेष राज्य बलों और ख़ुफ़िया शाखाओं को मज़बूत करने के लिए 371 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। 246 सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण के लिए 620 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त, गतिशीलता बढ़ाने, नाइट लैंडिंग हेलीपैड, निगरानी प्रणाली, ड्रोन ट्रैकिंग, एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स, जीआईएस मैपिंग, ख़ुफ़िया तंत्र के उन्नयन आदि पर भी भारी राशि खर्च की गई।

रेड कॉरिडोर से विकास कॉरिडोर तक

निर्णायक कारक अभूतपूर्व केंद्र-राज्य समन्वय रहा है, जो अब केवल समय-समय पर होने वाले सहयोग से आगे बढ़कर एक संस्थागत साझेदारी में बदल गया। इस परिवर्तन की बागडोर गृह मंत्रालय के हाथों में रही है। नियमित सुरक्षा समीक्षा, संयुक्त परिचालन योजना, ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने की व्यवस्था और प्रभावित राज्यों को लक्षित सहायता प्रदान करके, गृह मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों में एक ही उद्देश्य को बनाए रखने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के ज़रिए सरकार का लक्ष्य 'रेड कॉरिडोर' के दौर को समाप्त करना है और उसकी जगह सड़कों, स्कूलों तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) जैसी विकास परियोजनाओं को स्थापित करना है ताकि नक्सलवाद के प्रभाव को स्थायी रूप से खत्म किया जा सके।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की रणनीति में अब स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतने पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सशस्त्र हिंसा को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों का राज्य व्यवस्था पर विश्वास बहाल करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। कई क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन ने आदिवासी समुदायों तथा वंचित वर्गों के साथ बेहतर संवाद और सहभागिता स्थापित करने की दिशा में काम किया है। जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, नागरिक सहायता अभियानों और जवाबदेह प्रशासन ने उस अलगाव की भावना को कम करने में मदद की है जिसका फायदा उग्रवादी पहले उठाते थे।

दुर्गम क्षेत्रों में सतर्कता की निरंतर आवश्यकता

पहले नक्सल-प्रभावित रहे कई ज़िलों में नक्सली हिंसा में आई कमी इस बात का प्रमाण है कि इस रणनीति से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जिन क्षेत्रों को कभी उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था, वहां अब शासन व्यवस्था बहाल हो गई है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ी है। पहले अशांत रहे क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए चुनाव इस परिवर्तन का सशक्त प्रतीक हैं। नक्सल-मुक्त भारत की उपलब्धि के साथ, भारत ने एक ऐतिहासिक पड़ाव हासिल किया है। फिर भी, उग्रवाद के कुछ क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं, विशेष रूप से उन दुर्गम इलाकों में जहाँ चरमपंथी समूह फिर से संगठित होने का प्रयास करते हैं इसलिए निरंतर सतर्कता आवश्यक है। नक्सल-रोधी अभियानों की सफलता तभी स्थायी सिद्ध हो सकती है जब उसके साथ निरंतर विकास, उत्तरदायी शासन और संस्थागत सुदृढ़ता भी सुनिश्चित की जाए।

आगे बढ़ते हुए, नक्सल विरोधी अभियान से मिले अनुभव आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। पहला, सुरक्षा संबंधी कदम तब सबसे अधिक प्रभावी होते हैं जब उन्हें विकास और सुशासन के साथ जोड़ा जाए। दूसरा, जटिल और विभिन्न क्षेत्रों में फैले खतरों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मज़बूत समन्वय अनिवार्य है। तीसरा, विशेष रूप से गृह मंत्रालय जैसी संस्थाओं के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक रणनीतिक एकरूपता प्रदान कर सकता है, भले ही संचालन की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्यों के पास हो और चौथा, सीआरपीएफ तथा अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे पेशेवर और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाले सुरक्षा बल देश की आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ बने रहेंगे।

समन्वित शासन प्रबंधन की एक मिसाल

इस प्रकार, 'नक्सल-मुक्त भारत' की कहानी केवल सैन्य या पुलिस की कामयाबी तक सीमित नहीं है। यह समन्वित शासन प्रबंधन की एक मिसाल है। यह दर्शाती है कि किस प्रकार राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, पेशेवर सुरक्षा अभियान और विकास के प्रति प्रतिबद्धता मिलकर लंबे समय से चली आ रही उग्रवादी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे समाप्त कर सकते हैं। इस अभियान में राज्य पुलिस ने अग्रणी भूमिका निभाई है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) - विशेष रूप से सीआरपीएफ (सीआरपीएफ) ने एक मज़बूत परिचालन आधार के रूप में कार्य किया, जबकि गृह मंत्रालय ने वह रणनीतिक दिशा प्रदान की जिसने पूरे ढांचे को एकजुट बनाए रखा।

जैसे-जैसे भारत नक्सल-मुक्त राष्ट्र के लक्ष्य के करीब पहुँच रहा है, यह उपलब्धि सहकारी संघवाद की शक्ति, सुरक्षा बलों की पेशेवर क्षमता और भारतीय राज्य की उस स्थायी सामर्थ्य का प्रमाण बनकर उभरती है, जिसके माध्यम से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांति, व्यवस्था और विकास को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार, 'नक्सल-मुक्त भारत' केवल सुरक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय संकल्प और लोकतांत्रिक दृढ़ता की पुनर्पुष्टि भी है। ❑